











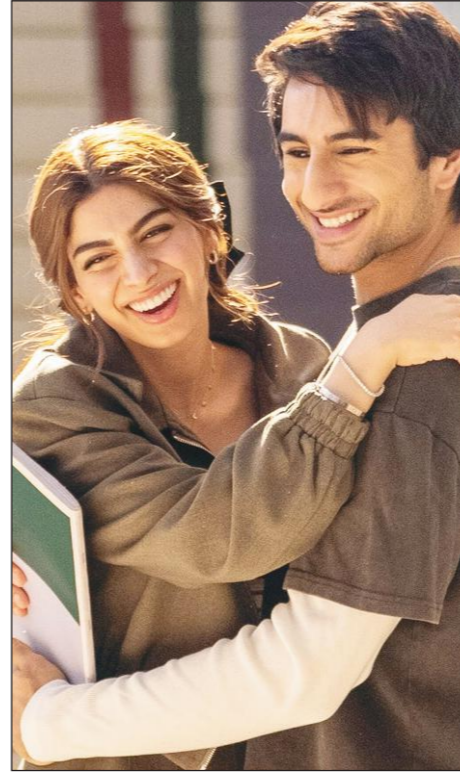


# मलाइका अरोड़ा एक मिस्ट्री मैन संग, स्पेन में



बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा मलाइका अरोड़ा अपनी प्रोफेशनल बातों से ज्यादा अपनी पर्सनल बातों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें 19 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। पहले पिछले साल 11 सितंबर को अपने पिता अनिल अरोड़ा की मौत और उसके बाद एक्टर अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रही मलाइका अरोड़ा, 'चल छैया छैया' और 'मुन्नी बदनाम हुई' 'अनारकली डिस्को चली', 'ढोलना', 'आप जैसा कोई', 'काल धमाल', 'माही वे' जैसे सुपरहिट आइटम साँगा में अपनी डासिंग स्किल्स और खासकर अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। पिछली बार मलाइका अरोड़ा को साँगा 'येक नंबर' में देखा गया था। मलाइका अरोड़ा अब तक अनेक डास रिप्लिटी शो में जज के किरदार में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत अवतार में नजर आ चुकी हैं। 2022 में मलाइका अपना शो 'मूविंग इन विद मलाइका' लेकर आई थीं। इसमें उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए भी देखा गया था। इस कि. रदार में भी फैंस ने उन्हें काफी पसंद किया। हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे अरहान खान के साथ मिलकर एक 'स्कार्लेट हाउस' नाम से रे. स्टोरेज शुरू किया है। इस तरह मलाइका अब एक एक्ट्रेस के साथ एक बिजनेस वुमन भी बन चुकी हैं। मलाइका 1998 में सलमान खान के मझले भाई अरबाज के साथ शादी की थी। शादी के लगभग 20 साल बाद 2017 में उन्होंने अरबाज खान से तलाक ले लिया। अरबाज से अलग होने के बाद 2018 में उन्होंने 11 साल छोटे एक्टर अर्जुन कपूर को डेट करना शुरू किया। पहले दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। मलाइका और अर्जुन इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे। दोनों ने साल 2019 में 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' की स्क्रिनिंग पर अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म किया था। उसके बाद मलाइका ने इसे अपने इंस्टा अकाउंट पर भी ऑफिशियल कर दिया। लेकिन 6 साल की डेटिंग के बाद मलाइका ने अर्जुन कपूर से अचानक रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद से ही मलाइका अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में छा गईं। मलाइका अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती हैं। वो टीवी और फिल्मों में लगातार काम कर रही हैं। अपने ग्लैमरस लुक और फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। मलाइका अरोड़ा इतनी अधिक खूबसूरत और फिट हैं कि यदि वे चाहती तो बतौर लीड एक्ट्रेस एक्टिंग करियर की शुरुआत करते हुए बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस के लिए खतरा बन सकती थीं। लेकिन मलाइका ने इससे बिलकुल अलग एक नई राह चुनी। मलाइका अरोड़ा ने भले ही कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन अपने लटकों-झटकों की वजह से बॉलीवुड पर छाई रहती थी। उनका ग्लैमरस अंदाज अक्सर फैंस को उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नजर आता रहता है। कभी वह शॉर्ट ड्रेस में नजर आती हैं तो कभी बिकिनी में फैंस के दिलों पर छुरियां चलाती हैं। अर्जुन कपूर से अलगाव होने के बाद कहा जा रहा है कि मलाइका की लाइफ में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी है। हाल ही में मलाइका दारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में वह एक मिस्ट्री मैन संग, स्पेन में क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए नजर आईं। इन तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान खींचा। हालांकि तस्वीरों में उस मिस्ट्री मैन का चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था लेकिन अब एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका इस मिस्ट्रीमैन को डेट कर रही हैं।

इब्राहिम अली खान की पहली फिल्म 'नादानियां' सात मार्च को नेटफिलक्स पर होगी रिलीज



नयी दिल्ली, अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान की पहली फिल्म 'नादानियां' सात मार्च को 'नेटफिलक्स' पर रिलीज होगी। ऑनलाइन मंच ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की। फिल्मकार करण जोहर की निर्माण कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की डिजिटल इकाई धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने इसका निर्माण किया है। शौना गौतम इसके निर्देशक हैं। 'नेटफिलक्स' ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर एक वीडियो साझा करते हुए फिल्म की रिलीज तारीख की घोषणा की। उसने लिखा, "कुछ-कुछ होता है ऐसी नादानियां देख कर। फिल्म 'नादानियां' देखें सात मार्च को केवल नेटफिलक्स पर।" फिल्म में इब्राहिम अली के साथ खुशी कपूर भी मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा इसमें अभिनेत्री महिमा चौधरी, दीया मिर्जा, अभिनेता सुनील शेट्टी और जुगल हंसराज भी नजर आएंगे।

स्कोडा के ब्रांड एम्बेसडर बने अभिनेता रणवीर सिंह

नयी दिल्ली, वाहन विनिर्माता स्कोडा ऑटो इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक पेद्रु जेनेबा ने कहा कि रणवीर सिंह की शक्ति, जो फिल्मी पर्दे पर और असल जिंदगी में भी बहुत ऊर्जा और प्रतिभा से भरी हुई है, वह स्कोडा के ब्रांड के जोश और मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती है। स्कोडा ने कहा है कि यूरोप के बाहर भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। स्कोडा ने पहले ही 2026 तक देश में सालाना एक लाख कारों बेचने की योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है।

'इमरजेंसी' 17 मार्च से नेटफिलक्स पर प्रसारित होगी : कंगना रनौत



नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 17 मार्च से नेटफिलक्स पर प्रसारित की जाएगी। यह फिल्म अपने संसार प्रमाणपत्र तथा सिख समुदाय को गलत ढंग से प्रस्तुत करने के आरोपों के कारण विवादों में रही और कई बार रिलीज टलने के बाद 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आपातकाल के समय पर आधारित इस फिल्म में कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। वह इसकी निर्देशक एवं निर्माता भी हैं। रनौत ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर फिल्म की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "17 मार्च से नेटफिलक्स पर..."




Your words can help in **digital empowerment** of rural India!

Participate in the

# SLOGGAN WRITING COMPETITION

for Branding-Digital India Common Services Centers (DICSC)

& contribute to **India's digital transformation**

Visit: [Mygov.in](http://Mygov.in)










## Dr. Jitendra Singh Inaugurates PMSSY Building at SCTIMST, Highlights India's Healthcare Transformation



**New Delhi, Focus News:** Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated the 'Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana' (PMSSY) driven upgraded Super specialty Neurosurgery and Cardiovascular Surgery state-of-the-art Building Block at Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST) here and emphasized that the Modi Govt's new initiatives are aimed at making quality healthcare affordable, accessible across sections of society. The Minister described the institute as a model of synergy between science, technology and medical advancements, aligned with Prime Minister Narendra Modi's vision of integrated holistic approach. Speaking at the event, Dr. Jitendra Singh praised SCTIMST for emerging as a center of excellence in both healthcare as well as research and development of new devices, instruments and medical procedures at cost-effective rates. He highlighted that the institute, functioning under the Department of Science and Technology, embodies the "whole-of-government" approach, fostering collaboration between the Ministry of Health and the Ministry of Science and Technology. He acknowledged the role of scientists, researchers, and healthcare professionals in positioning India as a leader in medical research and innovation. Union Minister Dr. Jitendra Singh speaking after inaugurating the new upgraded neurosurgery and cardiovascular surgery block at Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) at Thiruvananthapuram. Dr. Jitendra Singh noted that the PMSSY initiative is part of a broader effort to strengthen India's healthcare infrastructure. "The scheme is designed to provide quality medical care while promoting indigenous innovation in health-related R&D," he said. The new PMSSY Building will significantly enhance the capacity of SCTIMST, offering advanced healthcare facilities, specialized medical research laboratories, and improved infrastructure for patient care. It will also serve as a hub for high-end medical training, facilitating knowledge-sharing among medical professionals. He linked the project to the larger healthcare ecosystem that includes the Ayushman Bharat initiative, the world's largest health insurance program, and the newly announced universal health cover for citizens above 70 years. Stressing the need for integrating modern medical advancements with traditional healthcare approaches, Dr. Jitendra Singh underscored the importance of digital health initiatives, artificial intelligence in diagnostics, and genome-based therapies. Highlighting India's achievements in biotechnology, Dr. Jitendra Singh pointed to the success of the indigenous COVID-19 vaccine, the development of the HPV vaccine for cervical cancer, and breakthroughs in gene therapy. "India has transitioned from being an importer to a leader in preventive healthcare, gaining global recognition in biomanufacturing and medical research," he stated. He further emphasized the need for continued investments in healthcare R&D, ensuring that India remains at the forefront of medical advancements.

Dr. Jitendra Singh also underscored the need for strategic specialization, suggesting that SCTIMST focus on becoming a global leader in neurosurgery and cardiovascular research to enhance its international recognition. "A distinct identity in a specialized field attracts global attention and medical tourism, much like leading institutes in the U.S.," he added. He encouraged scientists and medical professionals to undertake collaborative research projects with global institutions to expand knowledge and expertise. The Minister stressed that while India has made remarkable progress in bridging the rural-urban divide in disease patterns, healthcare accessibility remains a challenge. He reiterated the government's commitment to expanding medical services through new AIIMS institutions and upgraded medical colleges, ensuring affordable and high-quality treatment. He also called for leveraging telemedicine and mobile health units to extend healthcare services to remote regions, making quality healthcare accessible to all. The event saw participation from key stakeholders in the medical and scientific community, including senior officials from the Ministry of Science and Technology, medical practitioners, and researchers. The inauguration of the PMSSY Building at SCTIMST marks another milestone in India's journey towards a self-reliant and globally competitive healthcare infrastructure. Dr. Jitendra Singh reaffirmed the government's continued support for initiatives that strengthen India's health ecosystem, positioning the country as a leader in medical innovation and patient care.

## TRIFED enters into MOUs with Reliance Retail, HCL Foundation, and Torajamelo Indonesia for entrepreneurship development of tribals

**New Delhi, Focus News:** TRIFED has been taking various visionary steps towards tribal empowerment and to bring the tribal population towards mainstream empowerment. One such initiative in this direction is partnerships of TRIFED with Reliance Retail, HCL Foundation, and Torajamelo Indonesia to facilitate tribal businesses for elevating lakhs of tribals from the rural India to a mainstream national level. Memoranda of Understanding (MoUs) were signed on 19th February during the ongoing flagship event 'Aadi Mahotsav,' held at Major Dhyana Chand National Stadium in the National Capital from 16 to 24 February 2025, marking a pivotal step in ensuring the implementation of the B2B approach and augmentation of the tribal product market. These MoUs were exchanged by General Managers of TRIFED with Mr. Pradeep Ramachandran, Senior Vice President of Reliance Retail, Dr. Nidhi Pundhir, Global CSR Head of HCL Foundation and Ms Aparna Saxena Bhatnagar, CEO of Torajamelo, Indonesia respectively in the presence of Shri Ashish Chatterjee, Managing Director, TRIFED on various aspects leading to the socio-economic development of tribal communities across the country. The principal objective of the MoU with Reliance Retail is to supply tribal products in bulk to Reliance Retail; this collaboration will also help to provide sustainable sourcing initiatives, branding, and promotions of tribal products. The HCL Foundation will assist in establishing long-term collaborations with tribal artisans to provide capacity building and new training to enhance the product portfolio and promotion of existing products through their various platforms. The collaboration with Torajamelo will assist in expanding international marketing and sales channels for Indian tribal products in Indonesia. This will not only open up new markets for Indian tribal artisans but also foster a unique cultural exchange between artisans. TRIFED has been organizing "Aadi Mahotsav - National Tribal Festival" to provide direct market access to the tribal master craftsmen and women in large metros and State capitals. The theme of the festival is "A Celebration of the Spirit of Entrepreneurship, Tribal Craft, Culture, Cuisine, and Commerce," which represents the basic ethos of tribal life.

Droupadi Murmu, Hon'ble President of India, has inaugurated the festival in the August presence of Shri Jual Oram, Union Minister for Tribal Affairs, Shri Durga Das Uikay, Union Minister of State for Tribal Affairs Ms. Bansuri Swaraj, Hon'ble Member of Parliament, New Delhi and other dignitaries on 16th February 2025. With this and several other ventures, TRIFED continues further with its efforts to enable the economic welfare of these communities and bring them closer to mainstream development.

## We aim to auction as many critical mineral blocks as possible by 2031: Satish Chandra Dubey, Union Minister of State for Mines and Coal

**New Delhi, Focus News:** India plans to maximise the auction of critical mineral blocks by 2031, advancing its strategic push to secure domestic supply chains for minerals essential to the country's green energy and technology sectors. Speaking at a FICCI conference, Critical Minerals Matrix, Union Minister of State for Mines and Coal, Satish Chandra Dubey, outlined the government's strategic approach to reducing import dependency for critical minerals. The announcement follows the recent launch of the National Critical Minerals Mission, which has allocated ₹34,300 crore over seven years to strengthen India's position in the critical minerals sector. "The government has already auctioned 24 critical mineral blocks domestically, and we aim to auction as many critical mineral blocks as possible by 2031," the minister said. The initiative forms part of a broader strategy to enhance India's mineral security and reduce vulnerability to international supply chain disruptions. The minister emphasised the role of public-private partnerships in achieving these objectives. "We must work as complementary partners and as a team to build a self-reliant India," Minister Dubey stated, urging increased private sector involvement in mineral exploration and extraction activities. The announcement comes amid growing



concerns about critical mineral supply chains, particularly for materials essential to electric vehicles, electronics manufacturing, and renewable energy systems. Welcoming the Minister at the conference, Jyoti Vij, Director General, FICCI, highlighted the economic significance of critical minerals. She emphasised that the launch of the National Critical Minerals Mission was timely, coinciding with increased budget emphasis on critical minerals, and would help boost production, recycling, and global acquisition of critical mineral assets to reduce dependence on imports and secure stable supply chains. Vij announced the constitution of the FICCI Committee on Critical Minerals, which will

work closely with the government and the industry stakeholders to address sector issues and leverage opportunities.

On occasion, Dhiraj Nayyar, Group Chief Economist, Vedanta, highlighted the urgency of developing domestic resources, noting that electric vehicles require six times more minerals than conventional cars, whilst offshore wind infrastructure demands nine times more minerals than traditional power plants. "We don't want to move from import dependence on oil to import dependence on critical minerals. The key is exploration," Nayyar emphasised, calling for streamlined approval processes and increased flexibility in land allocation for exploration activities.

## IWAI Board commissions feasibility study for Urban Water Transport System in 17 cities



**New Delhi, Focus News:** The Inland Waterways Authority of India (IWAI) Board – in its 196th Board Meeting – took a key decision to carry out feasibility study for developing Urban Water Transport System in various cities. The Board decided to explore Water Metro in full or part in 17 cities across 12 states of India. Kochi Metro Rail Limited (KMRL) have been appointed to carry out the feasibility study. This initiative will provide a robust and sustainable urban transport system by utilising existing navigable waterways. The Water Metro model represents a breakthrough in urban water transportation, offering safe, efficient, and environmentally-friendly alternatives to conventional modes of transport. Leveraging India's rich network of rivers, canals and other water bodies, the project will focus on cities with significant potential for urban water transport system. The 17 cities chosen by IWAI, in consultation with Ministry of Ports, Shipping and Waterways, for developing water metro include - Ayodhya, Dhubri, Goa, Guwahati, Kollam, Kolkata, Prayagraj, Patna, Srinagar, Varanasi, Mumbai, Vasai, Mangalore (Gurupura River), Gandhinagar-Ahmedabad (Sabarmati River), Alleppey in Kerala as well as Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands where inter-island ferry services could transform connectivity. The Urban Water Transport System will connect mainland and adjoining municipalities/panchayat areas/islands through waterways and integrate the system with other modes of transport. Besides, it will promote tourism and regional economic growth. It will employ non-polluting and sustainable measures through energy-efficient electric ferries, modernised terminals and ensure seamless multimodal connectivity. Under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and the able guidance of Minister of Ports, Shipping and Waterways Shri Sarbananda Sonowal, IWAI has been making several infrastructural interventions to develop waterways as a robust engine of growth. With its concerted efforts, IWAI is expanding its footprint throughout the country – from Arunachal Pradesh in the East to Gujarat in the West and Jammu and Kashmir in the North to Kerala in the South. In line with Harit Nauka guidelines, the Authority has taken multiple green initiatives which includes procurement of electric catamarans for passenger ferries.

## Ministry of Defence inks a contract worth ₹1220.12 Cr with Bharat Electronics Limited for procurement of 149 Software Defined Radios for Indian Coast Guard

**New Delhi, Focus News:**

The Ministry of Defence has signed a contract with M/s Bharat Electronics Limited (BEL), Bengaluru on 20th February, 2025, for procurement of 149 Software Defined Radios for Indian Coast Guard at a total cost of ₹1220.12 Cr under Buy (Indian-IDD) category. These state-of-the-art radios will enable secure and reliable information sharing,



collaboration, and situational awareness through high-speed data and secure voice communication. This will strengthen the Indian Coast Guard's capability to fulfil its core responsibilities, including maritime law enforcement, search and rescue operations, fisheries protection, and marine environment protection. Additionally, these radios will enhance interoperability for joint operations with the Indian Navy. The project is a strategic step toward bolstering the Coast Guard's operational capabilities and supporting the Government of India's Blue Economy objectives by reinforcing maritime security. Aligning with the Atmanirbhar Bharat initiative, the contract will enhance the country's manufacturing capabilities for advanced military-grade communication systems, generating employment opportunities and fostering expertise development.

## Ministry of Defence signs ₹697.35 Cr contracts with ACE Ltd & JCB India Ltd for procurement of 1868 Rough Terrain Fork Lift Truck for Armed Forces

**New Delhi, Focus News:** The Ministry of Defence has signed contracts with M/s ACE Limited and M/s JCB India Limited in presence of Defence Secretary Shri R K Singh for procurement of quantity 1868 Rough Terrain Fork Lift Truck (RTFLT) at a total cost of ₹697.35 crore for Indian Army, Indian Airforce and Indian Navy. Rough Terrain Fork Lift Truck (RTFLT) is a critical equipment which will assist in various combat and logistics support tasks by avoiding manual handling of enormous number of stores and thus enhancing the operational effectiveness of Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. The present case being a Buy (Indian) case will enhance national defence equipment manufacturing capabilities. This project has immense potential of direct and indirect employment generation by encouraging MSME sector through component's manufacturing. The procurement marks a pivotal step towards modernising India's defence infrastructure and empowering indigenous industries, which will be a proud flag-bearer of 'Aatmanirbhar Bharat'.

## STEEL CUTTING OF THIRD FLEET SUPPORT SHIP FOR INDIAN NAVY

**New Delhi, Focus News:**

Steel Cutting ceremony of third of the five Fleet Support Ships (FSS) was held at M/s L&T Shipyard, Kattupalli on 20 Feb 25, in the presence of R Adm Satish Shenai, Flag Officer Commanding Tamil Nadu and Puducherry Naval Area and senior officials



from Indian Navy, Hindustan Ship Yard Limited (HSL) and M/s L&T. The Indian Navy had signed a contract with HSL for acquisition of Five Fleet Support Ships (FSS) in Aug 2023, with delivery commencing mid-2027. Showcasing the strength of Public - Private partnership, HSL has contracted part construction of two FSS to M/s L&T Shipyard, Kattupalli to effectively utilise country's shipbuilding capacity and meet stringent timelines for delivery. On induction, the FSS will bolster the Blue Water capabilities of the Indian Navy through replenishment of Fleet ships at sea. These ships, with a displacement of more than 40,000 tons, will carry fuel, water, ammunition and stores enabling prolonged operations without returning to harbour, thus enhancing the Fleet's extended reach and mobility. In their secondary role, these ships would be equipped for Humanitarian Aid and Disaster Relief (HADR) operations for evacuation of personnel and expeditious delivery of relief material during natural calamities. With a completely indigenous design and sourcing of the majority of equipment from indigenous manufacturers, this project will boost the Indian Shipbuilding Industry and is in consonance with GoI initiatives of Aatmanirbhar Bharat, Make in India and Make for the World.

NHRC, India organised a meeting of the Core Group on Women on the theme 'Empowering ASHAs: Securing the right to work with dignity'



**New Delhi, Focus News:** The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a core group meeting in hybrid mode on women on the theme 'Empowering Accredited Social Health Activists (ASHAs): Securing the right to work with dignity' at its premises in New Delhi. It was chaired by the NHRC, India Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian in the presence of Member, Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, Secretary General, Shri Bharat Lal, senior officers, experts, and ASHAs. Addressing the participants, Chairperson, Justice V. Ramasubramanian highlighted the remarkable contributions made by ASHAs over the past 20 years towards improvements in the healthcare sector in the country. He emphasised that the significant impact of ASHAs has led to notable progress in reducing neonatal and infant mortality rates. They showed that individuals without formal education can still be trained to become skilled workers. He also noted that while there are many educated people today, the number of skilled workers is decreasing. This gap is being addressed by the ASHA scheme. However, he pointed out that ASHAs' have been stating that their remuneration is not in proportion to their contribution to society. The irony is that at times, those who contribute the most often receive the least; those who care for the marginalized end up being marginalized themselves. Justice Ramasubramanian said that public health and fixing of minimum wages is a subject coming under the State. Population control and family planning fall under the Concurrent list. Hence, there should be a collaborative effort between the Centre and State Governments to address the issues concerning ASHAs' welfare. He also called for a concrete policy and actionable measures for improving the working conditions and living standards of ASHAs. NHRC, India Member, Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi said that the ASHAs are the first responders to any distress related to pregnant women and children in the village areas before consultation with any doctors materializes. Therefore, their role as activists should be better recognized with adequate incentives, compensation, and security to ensure their right to life with dignity. Before this, while setting the agenda of the meeting and providing background, the Secretary General, Shri Bharat Lal highlighted the theme of the three technical sessions. These included: 'The Evolving Nature of Challenges faced by ASHA', 'Role of the Government in Protecting and Promoting the Rights of ASHAs', and 'Way Forward: Ensuring the Right to Work with Dignity for ASHAs.' He said that the Government has come up with various schemes for women's empowerment and given the contribution of ASHAs in primary healthcare, their issues such as low honorarium, excessive workload, and insufficient resources also need to be addressed. He highlighted their role during COVID-19 as frontline workers have been exemplary, which has also been acknowledged by the WHO. The speakers included Shri Saurabh Jain, Joint Secretary, MoHFW; Ms Pallavi Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Women & Child Development; Dr Shweta Khandelwal, Senior Advisor Jhpiego India; Ms Ruth Manorama, President, The National Alliance of Women (NAWO); Dr Sabiha Hussain, Professor and Director, Sarojini Naidu Center for Women's Studies, Jamia Islamia University; Ms. Vaishali Barua, National Coordinator, UN Women India; Ms Dipa Sinha, Visiting Professor, Azim Premji University; Ms Surekha Secretary, ASHA Workers' and Facilitators' Federation of India (AWFFI); Ms Sunita, ASHA Worker, Haryana, NHRC, India DG (I), Shri R Prasad Meena, Registrar (Law), Joginder Singh, Director, Lt Col Virender Singh among others.

**Some of the suggestions that emanated from the discussion included;**

- Need to consider granting ASHAs formal worker status with fixed monthly emoluments, social security, pensions, paid leave, etc.;
- Standardize honorarium/ wages across states, ensuring that honorariums align with minimum wage regulations;
- Replace incentive-based payment structure with a fixed amount plus performance-based benefits;
- Provide health insurance, maternity benefits, and accident coverage to ASHAs;
- Ensure free personal protective equipment (PPE), transport allowances, and access to clean rest areas during field visits;
- Enforce strict policies against harassment and violence, ensuring safe working conditions for ASHAs in all regions;
- Utilize Rs 49,269 crore (As of 2022) of unspent funds from the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act for childcare, elderly care, and ASHA welfare;
- Allocate Rs 70,051 crore health sector grants towards strengthening early childhood care and healthcare workers' training;
- Establish state-funded creches at primary health centres and community centres to support ASHAs who are also primary caregivers at home;
- Develop structured career pathways for ASHAs to transition into higher-paying healthcare roles, such as nursing, midwifery, and public health administration;
- Provide regular skill enhancement training in disease surveillance, mental health counseling, and emergency medical response;
- Introduce bridge courses in collaboration with medical colleges and universities to certify ASHAs for formal healthcare roles;
- Incentivize private sector investments in childcare and elderly care infrastructure, with tax benefits for employers offering workplace childcare solutions;
- Promote cooperative models, like the SEWA model, to ensure ASHAs have decision-making power over wages and working conditions; and
- Foster public-private partnerships to expand affordable community-based care services, creating decent job opportunities for ASHAs.

FIRST TRAINING SQUADRON OF INDIAN NAVY ARRIVED AT CAM RANH BAY, VIETNAM

**New Delhi,** Building Bridges of friendship whilst training young minds, the ships of First Training Squadron - INS Tir and ICGS Veera arrived at Cam Ranh Bay, Vietnam on 20 Feb 25. The ships received a warm welcome by the Vietnam People's Navy and members of Indian mission at Vietnam. The visit is poised to further strengthen the longstanding friendship and growing partnership between the two maritime nations. During the port call, various cross training visits, professional and community interactions including a visit to Vietnam Naval Academy are planned.

India Assumes Chairmanship of Bay of Bengal Inter-Governmental Organisation at the 13th Governing Council Meeting in Malé, Maldives

**New Delhi, Focus News:** In a historic move, India assumed Chairmanship of Bay of Bengal (BOB) Inter-Governmental Organisation from Bangladesh at the 13th Governing Council Meeting at Malé, Maldives today, in the presence of senior government representatives from Sri Lanka, Maldives and Bangladesh. The event was part of the high-level conference 'Policy Guidance for Mainstreaming Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Small-Scale Fisheries', hosted by the Ministry of Fisheries & Ocean Resources of the Maldives government, in collaboration with the Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organisation (BOBP-IGO), that has been successfully convened from February 20 to 22, 2025, in Lankanfinolhu, Maldives. The Indian delegation, led by Dr. Abhilaksh Likhi, Secretary, Department of Fisheries, Government of India (GoI) assumed the Chair during the event. Secretary, Department of Fisheries highlighted that India is committed to upholding and building upon the achievements of the Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organisation (BOBP-IGO) as the leadership transitions from Bangladesh to India. He assured that the Department of Fisheries (GoI) would diligently work towards elevating the success of BOBP-IGO to newer heights and will be forthcoming in providing definitive guidance for all future endeavours for the development of fisheries sector across all member countries.



Further, Dr. Abhilaksh Likhi underscored the importance of regional collaboration, and the crucial role India and other countries are playing in advancing the interests of the developing nations. Key areas of focus for increased regional co-operation include marine resource management, training & capacity building programs, research & policy advocacy, addressing Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, resolving regional issues etc. As India remains optimistic about receiving continued support and collaboration from Food and Agriculture Organization (FAO), Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), and other relevant organizations, Secretary, Department of Fisheries (GoI) urged all member nations to enhance and foster mutual support through exchange of knowledge, technology, experiences, data and best practices. The collaborations are expected to strengthen region's blue economy, harmonize economic development along with protection of marine ecosystem and help in poverty alleviation. During the meeting, Secretary, Department of Fisheries (GoI) highlighted India's developmental policies aimed at improving the well-being of small-scale fisheries and the sustainability measures being implemented under its various schemes and programs. With the successful culmination of this important event and India assuming Chair of the BoBP-IGO, it will be the endeavour of the Department of Fisheries, under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to not only lead the member nations in the most effective and efficient manner through collaborative efforts but also ensure that significant progress is made in the development of Small-scale fisheries (SSF) in the region.

Ministry of Mines classifies Barytes, Felspar, Mica and Quartz as Major Minerals

**New Delhi, Focus News:** The Ministry of Mines vide gazette notification dated 20th February, 2025 has shifted minerals Barytes, Felspar, Mica and Quartz from the list of minor minerals to the category of major minerals. This move follows the recent approval of the National Critical Mineral Mission by the Union Cabinet on 29th January, 2025. The Mission envisages exploration and mining of critical minerals within the country including recovery of these minerals from mines of other minerals, overburden and tailings. Quartz, Felspar and Mica are found in pegmatite rocks, which are an important source of many critical minerals such as Beryl, Lithium, Niobium, Tantalum, Molybdenum, Tin, Titanium, Tungsten, etc. These minerals have vital role in various new technologies, in energy transition, spacecraft industries, healthcare sector, etc. When the leases of Quartz, Felspar and Mica are granted as minor mineral leases, the lease holders do not declare existence of critical minerals or extract the critical minerals associated with it such as Lithium, Beryl, etc. as their primary objective is to use these minerals as minor minerals for construction, glass / ceramic making, etc. Consequently, the critical minerals associated with these minerals are neither getting extracted nor reported. Similarly, Baryte has various industrial applications which is used for oil and gas drilling, electronics, TV screens, rubber, glass, ceramics, paint, radiation shielding and medical applications. Baryte is used to make high density concrete to block x-ray emissions in hospitals, power plants, and laboratories. Baryte often occurs as concretions and vein fillings in limestone and dolostone. It is found in association with ores of Antimony, Cobalt, Copper, Lead, Manganese and Silver. Baryte with iron ore occurs in pocket type of deposit which cannot be mined in isolation. While mining either of the minerals, the production of associated mineral is inevitable. In view of the importance of these minerals, the Inter-Ministerial Committee on Mines & Minerals Sector constituted under the chairmanship of Dr. V. K. Saraswat, Member NITI Aayog, recommended that these minerals be shifted from the list of minor minerals to the category of major minerals.






Your words can help in digital empowerment of rural India!

Participate in the

# SLOGAN WRITING COMPETITION

for Branding-Digital India Common Services Centers (DICSC)

& contribute to India's digital transformation

Visit: Mygov.in



कृषि और ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए: धनखड़



नयी दिल्ली, फोकस न्यूज़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण आबादी अवसर और जिम्मेदारी दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास (एएआरडीओ) सम्मेलन के 21वें आम सत्र के उद्घाटन अवसर पर उपराष्ट्रपति ने परेशानियों को कम करने के लिए भी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र 3.6 अरब लोगों का पोषण करते हैं, जिनमें 89.4 करोड़ भारतीय ग्रामीण शामिल हैं, जो "हमारे अवसर और जिम्मेदारी दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं"। उन्होंने कहा, "हमारी बुद्धि के लिए चुनौती विघटनकारी प्रौद्योगिकी के उद्भव के रूप में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग... औद्योगिक क्रांति से कम नहीं है।" उपराष्ट्रपति ने कहा, "वे कठिन चुनौतियाँ पेश करती हैं, लेकिन साथ ही अनेक अवसर भी लेकर आती हैं, बशर्ते हम उनका लाभ उठाना सीखें।" धनखड़ ने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, "यदि हम इन विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र तथा संपूर्ण विश्व के अधिक से अधिक लाभ के लिए उपयोग में ला सकें, तो मानवता अधिक सुरक्षित स्थान होगी।" उन्होंने कहा, "भारत ने कुछ प्रमुख पहल की हैं और उनमें से एक पहल 'डिजिटल इंडिया' है।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री वांग से मुलाकात



जोहानिसबर्ग, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यहां जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की दो दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में हैं। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "जोहानिसबर्ग में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आज सुबह सीपीसी पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात का अवसर मिला।" जयशंकर ने मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। यह बैठक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच हो रही है। जयशंकर ने बृहस्पतिवार को वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति पर चर्चा शीर्षक वाले जी-20 सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जी-20 विश्व की बढ़ती बहुध्रुवीयता का एक अहम मंच है। उन्होंने कहा, "वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति कठिन बनी हुई है।"

राहुल गांधी ने रायबरेली में की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, अगले विस चुनाव की तैयारी का आग्रह



रायबरेली (उप्र), फोकस न्यूज़, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे संगठन को मजबूत करने तथा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुएमऊ में गांधी से मुलाकात की और उन्हें विभिन्न मुद्दों, खासकर दलितों से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। रायबरेली में कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार गौतम ने कहा कि समुदाय का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सुबह गांधी से उनके भुएमऊ स्थित आवास पर मिला। गौतम ने कहा कि "हमने अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सामने आई कठिनाइयों के बारे में बताया। गौतम ने 'पीटीआई-वीडियो' को बताया, "सबसे बड़ी चिंता यह है कि नगर निकायों में कार्यरत

वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी अब भी बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने को मजबूर हैं, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है।" गौतम ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें प्रेरित किया और पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए 2027 के चुनावों के लिए जोरदार तैयारी करने की जरूरत पर जोर दिया। रायबरेली कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सर्वोत्तम कुमार मिश्रा ने गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि उनकी ईमानदारी, दूरदर्शिता और कार्य नैतिकता वर्णन से परे है। मिश्रा ने यह भी दावा किया कि बिहार चुनाव से पहले गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बैठक के बाद मिश्रा ने 'पीटीआई-वीडियो' को बताया कि गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता की बात ध्यान से सुनी और उनकी चिंताओं के समाधान की जरूरत पर जोर दिया। राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को रायबरेली का अपना दो दिवसीय दौरा शुरू किया।

रामानुजन महाविद्यालय में किया गया स्वास्थ्य मेला का आयोजन

नई दिल्ली। फोकस न्यूज़। रामानुजन महाविद्यालय में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। जिसके संयोजक डॉ मनोज दहिया, उप संयोजक डॉ शिप्रा यादव, डॉ ब्रजेश कुमार, समग्र समन्वयक डॉ सुनीता जेटली, छात्र समन्वयक गौरव आनंद। स्वास्थ्य मेला 2025 आरंभ कुलगीत से हुआ और विशिष्ट व्याख्यान की औपचारिक शुरुआत हुई मुख्य वक्ता के रूप में प्राचार्य प्रो. रसाल सिंह ने मुख्य वक्ता का अभिनेदन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ही प्रथम सम्पत्ति है और विद्यार्थियों को नि:शुल्क जांच कराने के लिए जागरूक किए। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉ डिम्पल चौधरी, डॉ कमलेश सैनी, डॉ बलराम रा. जपुनिया और डॉ सुनीता जेटली एसोसिएट प्रोफेसर आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय। स्वास्थ्य मेले में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार, नेत्र जांच, दंत चिकित्सा, रक्तचाप, ई.सी.जी., बी.एम.आई., ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बी.एम. डी. आर. बी. एस., तनाव, परीक्षा का दबाव, अवसाद और चिंता से निपटने के उपाय बताए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. रसाल सिंह और विद्यार्थी और अध्यापक समेत सभी ने जांच कराई। स्वास्थ्य मेले में 18 विद्यार्थियों ने रक्तदान दिया, महाविद्यालय में 236 विद्यार्थी व शिक्षकों ने नि:शुल्क स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया। स्वास्थ्य ही जीवन की प्रथम सम्पत्ति है और विद्यार्थियों में बहुत ही उत्साह के साथ स्वास्थ्य में अपनी जांच कराई और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया।



देश में इस साल गेहूं की अच्छी फसल होगी: कृषि मंत्री चौहान



नयी दिल्ली, फोकस न्यूज़, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिक रकब में खेती और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण भारत में चालू रबी सत्र के दौरान गेहूं की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। भारत ने वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1,132.92 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया था। चौहान ने यहां संवाददाताओं से कहा, "इस साल हमारे यहां गेहूं का बंपर उत्पादन होगा। फसल की सेहत अच्छी है।" फसल वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) के रबी सत्र में गेहूं का रकबा 320 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल यह रकबा 315.63 लाख हेक्टेयर था। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी अधिक रकबे के कारण वर्ष 2024-25 में गेहूं का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक फसल की स्थिति अच्छी है और दिन-रात का तापमान सामान्य है। बृहस्पतिवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं की स्टॉक रखने की सीमा को कड़ा किया गया है। विभाग ने यह भी कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। वह कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। देश में उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह उचित हस्तक्षेप करता है। 31 मार्च तक लागू होने वाली संशोधित स्टॉक सीमा के अनुसार, व्यापारी एवं थोक विक्रेता पहले के 1,000 टन के मानदंड के मुकाबले केवल 250 टन गेहूं रख सकते हैं। खुदरा विक्रेताओं के लिए, स्टॉक सीमा को प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए चार टन तक संशोधित किया गया है। पहले यह सीमा पांच टन थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है।" बड़े खुदरा बिक्री श्रृंखला के लिए, प्रत्येक बिक्रीकेंद्र के लिए स्टॉक सीमा चार टन होगी, जो उनके सभी बिक्रीकेंद्र और डिपो पर अधिकतम मात्रा (चार गुना आ. उटलेट की कुल संख्या) टन स्टॉक के अधीन होगी। सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अद्यतन करना आवश्यक है। सरकार ने कहा कि कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती पाई गई, उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है, "यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।"



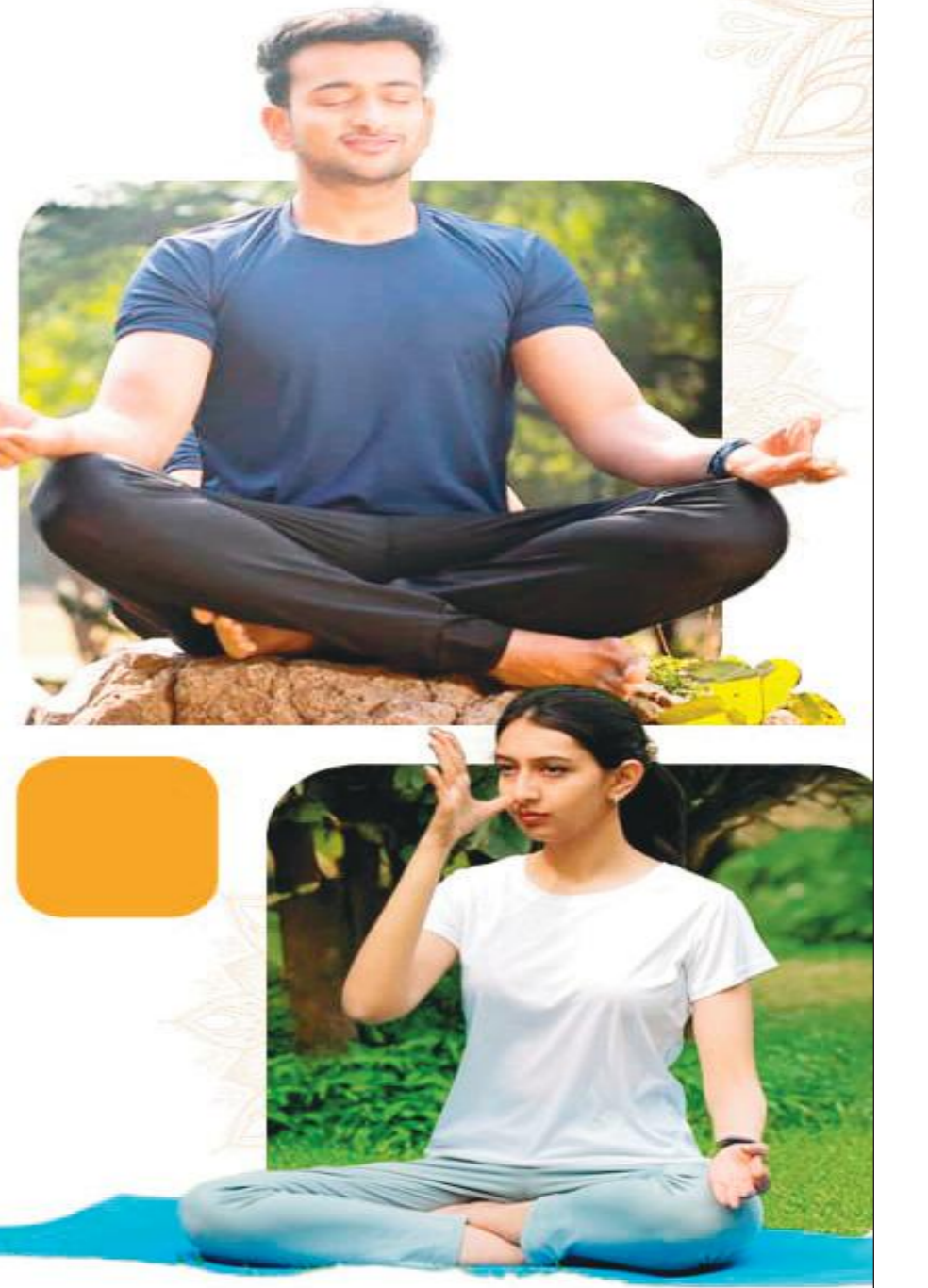
Celebrate the Power of Yoga  
in Transforming Lives

Nominate Now!

PRIME MINISTER'S  
AWARDS FOR

YOGA 2025

Honor excellence in promoting holistic  
health and wellness.



Visit : <https://innovateindia.mygov.in/>